

यूएस फेडरल रज़िर्व और भारतीय बाज़ार

हाल ही में यूएस फेडरल रज़िर्व (अमेरिका का केंद्रीय बैंक) ने ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी का संकेत दिया है। इससे भारतीय बाज़ारों में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है।

फेडरल रज़िर्व द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि यह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक नैतिक प्रभाव डालता है।

प्रमुख बंदि

■ फेडरल रज़िर्व और भारतीय बाज़ारों का सह-संबंध:

- भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वकिसति देशों जैसे- अमेरिका और कई (मुख्य रूप से पश्चिमी) यूरोपीय देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरें होती हैं।
- अतः वकिसति संस्थान, विशेष रूप से **वदिशी संस्थागत नविशक** (Foreign Institutional Investors- FIIs), कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उभरते देशों के सरकारी बॉण्ड में नविश करते हैं।
- जब फेडरल रज़िर्व अपनी घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर कम हो जाता है, इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाज़ार के लिये कम आकर्षक रह जाता है।
- यह भारत को **करेंसी कैरी ट्रेड** (Currency Carry Trade) हेतु कम आकर्षक बनाता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ धन के भारतीय बाज़ारों से बाहर निकलने और अमेरिका में वापस आने की उम्मीद की जा सकती है।
- करेंसी कैरी ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत अधिक उपज वाली मुद्रा में नविश के लिये कम उपज वाली मुद्रा का कम ब्याज दर के साथ व्यापार किया जाता है।
- इसलिये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है।

■ भारत पर बढी हुई ब्याज दरों का प्रभाव:

○ इक्वटी मार्केट पर प्रभाव:

- वैश्विक बाज़ार में डॉलर की बढ़ती कमी से **बॉण्ड यील्ड** (Bond Yields) में बढ़ोतरी होगी।
- इससे पहले, भारत में ऋण और इक्वटी बाज़ारों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बहिरवाह देखा गया था जो कि मजबूत डॉलर एवं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य प्रमुख देशों के बीच व्यापार युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताओं का प्रतफल था।

○ नरियात और वदिशी मुद्रा पर प्रभाव:

- भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में से एक है।
- डॉलर की तुलना में कमजोर रुपए के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का अधिक महंगा आयात होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागत-संचालित मुद्रास्फीति (Cost-Driven Inflationary) को बढ़ा सकता है जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- दूसरी ओर भारत के नरियात विशेष रूप से आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं को रुपए के संबंध में मजबूत डॉलर से कुछ हद तक लाभ होगा।
- हालांकि नरियात बाज़ार में मजबूत प्रतिस्पर्धा के कारण नरियातकों को पूरी तरह से एक समान लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

